प्रस्ताव 30 शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

- सात वर्षों के लिए $250,000 से अधिक की वार्षिक आय पर व्यक्तिगत आयकर को बढ़ाता है।
- चार वर्षों के लिए बिक्री और उपयोग कर में ¼ सेंट की वृद्धि करता है।
- अस्थायी कर राजस्व का 89% K–12 स्कूलों को और 11% कम्युनिटी कॉलेजों को आवंटित करता है।
- धन को प्रशासनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है, लेकिन स्थानीय स्कूल संचालन बोर्डों को, खुली बैठकों में और वार्षिक लेखा जांच के अंतर्गत, इस बारे में फैसला करने का अधिकार देता है कि धन को कैसे खर्च किया जाएगा।
- गारंटी देता है कि सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए धन का राज्य से स्थानीय सरकारों में पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- 2012–13 से लेकर 2016–17 तक लगभग $6 बिलियन सालाना का अतिरिक्त राज्य कर राजस्व। 2011–12, 2017–18, और 2018–19 में अतिरिक्त राजस्व की छोटी राशियां उपलब्ध होंगी।
- ये अतिरिक्त राजस्व राज्य के बजट में कार्यक्रमों में धन देने के लिए उपलब्ध होंगे। 2012–13 में लगभग $6 बिलियन की खर्च में कटौतियाँ, मुख्य रूप से शिक्षा कार्यक्रमों में, लागू नहीं होंगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अवलोकन

यह उपाय सभी करदाताओं के लिए राज्य बिक्रीकर की दरों और ऊपरी आय वाले करदाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर (PIT) की दरों में अस्थायी रूप से वृद्धि करता है। ये अस्थायी कर वृद्धि राज्य के बजट में वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए भुगतान के लिए अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराती है। राज्य का 2012–13 योजना बजट—जिसको विधायिका और गवर्नर द्वारा जून 2012 में अनुमोदित किया गया है—इस उपाय को पारित किया हुआ मानता है। मतदाताओं के इस उपाय को अस्वीकार करने की दशा में बजट में, तथापि, एक बैकअप योजना भी शामिल है जिसमें खर्च में कटौती ("ट्रिगर कटौती" के रूप में ज्ञात) की आवश्यकता शामिल है। यह उपाय कुछ राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों के हाल ही में स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण से संबंधित आवश्यकताओं को राज्य के संविधान में स्थापित करता है। चित्र 1 इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों को साराँशित करता है, जिन पर और अधिक विस्तार से चर्चा नीचे की गई है।

चित्र 1
प्रस्ताव 30 का अवलोकन

राज्य कर एवं राजस्व

- बिक्री कर की दर को चार साल के लिए प्रति डॉलर के लिए एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाता है।
- उच्च आय कर दाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों को सात वर्षों के लिए बढ़ाता है।
- 2012–13 से लेकर 2016–17 तक 2011–12, 2017–18, एवं 2018–19 में छोटी राशि के साथ अतिरिक्त वार्षिक राज्य राजस्व में लगभग $6 बिलियन उत्पन्न करता है।

राज्य व्यय

- यदि मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए, तो 2018–19 तक राज्य के बजट के संतुलन में मदद करने के लिए अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध।
- यदि मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो 2012–13 के बजट में $6 बिलियन की कटौती। 2018–19 तक राज्य के राजस्व में कमी।

स्थानीय सरकारी कार्यक्रम

- गारंटी देता है कि स्थानीय सरकारों को उन कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए सालाना कर राजस्व प्राप्त हों जिनके लिए 2011 में उनको राज्य द्वारा जिम्मेदारियों स्थानांतरित की गई।

राज्य कर एवं राजस्व

पृष्ठभूमि

सामान्य निधि राज्य का मुख्य संचालन खाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 (जो 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक चला) में सामान्य फंड का कुल राजस्व $93 बिलियन था। सामान्य फंड के तीन सबसे बड़े राजस्व स्रोत व्यक्तिगत आयकर, बिक्रीकर एवं कॉर्पोरेट आयकर थे।

बिक्रीकर। बिक्रीकर की दरें कैलिफोर्निया में जगह के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। वर्तमान में, औसत बिक्रीकर दर 8 प्रतिशत से बस थोड़ा उपर है। बिक्रीकर राजस्व का एक हिस्सा राज्य को जाता है, जबकि शेष स्थानीय सरकारों को आवंटित कर दिया जाता है। राज्य के सामान्य फंड में वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान $27 बिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ।

व्यक्तिगत आयकर। PIT वेतन, व्यापार, निवेश, और व्यक्तियों और परिवारों की अन्य आय पर लगने वाला कर है। राज्य की PIT दर कई आय कोष्ठकों में से प्रत्येक में किसी करदाता की आय के कुछ भागों पर 1 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक होती है। (उनको सीमांत कर दरों के रूप में जाना जाता है।) जैसे-जैसे आय बढ़ती है, उच्च सीमांत कर दरें ली जाती हैं। इस कर से उत्पन्न कर राजस्व—वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कुल $49.4 बिलियन—को राज्य के सामान्य फंड में जमा किया जाता है। इसके अलावा, $1 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना कर लागू होता है (संबद्ध राजस्व को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित करने के साथ)।

प्रस्ताव

2013 से लेकर 2016 तक बिक्री कर की दर को बढ़ाता है। यह उपाय प्रत्येक डॉलर से खरीदे गए सामान पर राज्यव्यापी बिक्री कर की दर को अस्थायी रूप से एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाता है। यह उच्च कर दर चार साल लिए प्रभावी होगी—1 जनवरी 2013 से लेकर 2016 के अंत तक।

2012 से लेकर 2018 तक व्यक्तिगत आयकर की दर को बढ़ाता है। जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, यह उपाय उच्च आय पर मौजूदा 9.3 प्रतिशत की PIT दर को बढ़ाता है। जैसे-जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है, अतिरिक्त सीमांत कर दरों में वृद्धि होगी। संयुक्त रूप से दाखिल करने वालों के लिए, उदाहरण के लिए, सालाना $500,000 से लेकर $600,000 की आय पर दर में कुल 1 प्रतिशत की वृद्धि कर उसको 10.3 प्रतिशत कर सीमांत कर दर में अतिरिक्त 1 प्रतिशत सीमाँत कर दर लागू होगी। इसी तरह, $600,000 एवं $1 मिलियन के बीच की सालाना आय पर एक अतिरिक्त 2 प्रतिशत सीमांत कर दर, और $1 मिलियन से अधिक की सालाना आय पर एक अतिरिक्त 3 प्रतिशत सीमांत कर दर लागू होगी, जो इन आय कोष्ठक पर कुल दरों को बढ़ाकर क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत कर देगा। ये नई कर दरें कैलिफोर्निया के 1 प्रतिशत PIT दाखिल करने वालों को प्रभावित करेंगी। (ये करदाता वर्तमान में राज्य व्यक्तिगत आय कर में लगभग 40 प्रतिशत भुगतान करते हैं)। कर की दरें सात सालों के लिए प्रभावी लागू होंगी—कर वर्ष 2012 में शुरू होकर कर वर्ष 2018 के अंत तक। (क्योंकि दर

चित्र 2

प्रस्ताव 30 के तहत वर्तमान और प्रस्तावित व्यक्तिगत आयकर दरें

एकल दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	संयुक्त दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	परिवार के मुखिया की दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	वर्तमान सीमांत कर दर[b]	प्रस्तावित अतिरिक्त वर्तमान सीमांत कर दर[b]
$0–$7,316	$0–$14,632	$0–$14,642	1.0%	—
7,316–17,346	14,632–34,692	14,642–34,692	2.0	—
17,346–27,377	34,692–54,754	34,692–44,721	4.0	—
27,377–38,004	54,754–76,008	44,721–55,348	6.0	—
38,004–48,029	76,008–96,058	55,348–65,376	8.0	—
48,029–250,000	96,058–500,000	65,376–340,000	9.3	—
250,000–300,000	500,000–600,000	340,000–408,000	9.3	1.0%
300,000–500,000	600,000–1,000,000	408,000–680,000	9.3	2.0
500,000 से अधिक	1,000,000 से अधिक	680,000 से अधिक	9.3	3.0

[a] दिखाए गए आय कोष्ठक 2011 के लिए प्रभाव में थे और भविष्य के वर्षों में मुद्रास्फीति के लिए उनको समायोजित किया जाएगा। एकल दाखिलकर्ताओं में शादीशुदा व्यक्ति और पंजीकृत घरेलू भागीदार (RDPs) भी शामिल हैं जो करों को अलग से दाखिल करते हैं। संयुक्त दाखिलकर्ताओं में शादीशुदा और RDP दंपत्ति शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से दाखिल करते हैं, और साथ ही आश्रित बच्चे के साथ पात्र विधवाएं या विधुर भी शामिल हैं।

[b] सीमांत कर दर सूचीबद्ध प्रत्येक कोष्ठक में कर योग्य आय पर लागू होती हैं। प्रस्तावित अतिरिक्त कर दरें 2012 में में शुरू होकर प्रभावी होंगी और 2018 के अंत में समाप्त हो जाएंगी। सूचीबद्ध वर्तमान कर दरों में $1 मिलियन से अधिक की कर योग्य पर आय पर लगने वाला अतिरिक्त 1 प्रतिशत की मानसिक स्वास्थ्य कर की दर की शामिल नहीं है।

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।

में वृद्धि 1 जनवरी 2012 को लागू होगी, प्रभावित करदाताओं को आने वाले महीनों में अधिक भुगतान करना होगा ताकि दरों में वृद्धि के कारण पूरे साल की भरपाई हो सके।) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर अभी भी $1 मिलियन से अधिक की आय पर लागू होती है। इसलिए, प्रस्ताव 30 के दर परिवर्तन इन करदाताओं की सीमांत PIT दर को 10.3 प्रतिशत से 13.3 प्रतिशत तक बढ़ाते हैं। इस मतदान पर प्रस्ताव 38 भी PIT दरों में वृद्धि करता है। पास का बॉक्स वर्णन करता है कि अगर दोनों उपायों को अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या होगा।

क्या होता है अगर मतदाता प्रस्ताव 30 व प्रस्ताव 38 दोनों को स्वीकृत कर देते हैं?

राज्य का संविधान निर्दिष्ट करता है कि अगर दोनों उपायों में संघर्ष होता है तो क्या होता है। यदि राज्यव्यापी मतदान में स्वीकृत दो उपायों के प्रावधानों में संघर्ष होता है तो संविधान निर्दिष्ट करता है कि अधिक "हाँ" के मत प्राप्त करने वाले उपाय के प्रावधान प्रबल होंगे। इस राज्यव्यापी मतदान में प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों व्यक्तिगत आय कर (PIT) की दरों में वृद्धि करते हैं, और इस तरह उनको परस्पर विरोधी के रूप में देखा जा सकता है।

उपाय व्यक्त करता है कि कर वृद्धि का केवल एक सेट ही प्रभावी होता है। प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों में यह स्पष्ट करने के लिए खण्ड हैं कि अगर दोनों उपाय पारित हो जाते हैं तो कौन से प्रावधान प्रभावी होंगे:

- ***यदि प्रस्ताव 30 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 30 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान अपनी सम्पूर्णता में लागू होंगे और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 38—प्रभावी नहीं होंगे।
- ***यदि प्रस्ताव 38 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 38 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान प्रबल होंगे और बिक्री कर या और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 30—प्रभावी नहीं होंगे। इस परिदृश्य के तहत, खर्च में कटौती, जिसे "ट्रिगर कटौती" के रूप में जाना जाता है, प्रस्ताव 30 की कर वृद्धि के प्रभावी न होने पाने के कारण प्रभावी होगी।

वित्तीय प्रभाव

2018–19 तक अतिरिक्त राज्य राजस्व। पाँच सालों के दौरान जिसमें बिक्री कर और PIT में वृद्धि प्रभावी होती है (2012–13 से लेकर 2016–17 तक), इस उपाय की कर वृद्धि से औसत वार्षिक राज्य राजस्व बढ़ोत्तरी का अनुमान लगभग $6 बिलियन है। उच्च कर दरों के चरणबद्ध तरीके से बाहर होने से 2011–12, 2017–18, और 2018–19 में राजस्व वृद्धि कम होने का अनुमान है।

राजस्व में एक साल से दूसरे साल काफी परिवर्तन हो सकता है। इस उपाय से राजस्व में होने वाली वृद्धि में कई बिलियन ड़लर का परिवर्तन हो सकता है—उपर अनुमानित राजस्व से उपर या नीचे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उपाय से अतिरिक्त राजस्व का अधिकाँश भाग ऊपरी आय वाले करदाताओं पर PIT की दर में होने वाली बढ़ोत्तरी से आता है। ऊपरी आय वाले करदाताओं द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली अधिकाँश आय कुछ मायनों में उनके निवेश और व्यापार से संबंधित होती है, न कि उनकी मजदूरी और उनके वेतन से। जहाँ ऊपरी आय वाले करदाताओं की मजदूरी और वेतन में कुछ हद तक उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी निवेश आय में शेयर बाजार के प्रदर्शन, आवास की कीमतों और अर्थव्यवस्था के आधार पर एक साल से अगले साल काफी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में $1 मिलियन से अधिक आय वाले करदाताओं से मानसिक स्वास्थ्य कर से आने वाली कुल आय 2009–10 में $730 मिलियन थी, जो पिछले वर्षों में आय से दो गुने से भी अधिक बढ़ गयी। करदाताओं की इस आय में होने वाले उतार-चढ़ाव और दर में वृद्धि के प्रति प्रतिक्रियाओं की अनिश्चितता के कारण इस उपाय से राजस्व में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना मुश्किल है।

राज्य व्यय

पृष्ठभूमि

राज्य सामान्य फंड कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। सामान्य फंड में जमा राजस्व विभिन्न किस्म के कार्यक्रमों का समर्थन करता है—जिसमें सार्वजनिक स्कूल, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक सेवाएं, और जेल शामिल हैं। स्कूल पर होने वाला खर्च राज्य बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य के मतदाताओं द्वारा इससे पहले पारित प्रस्तावों की आवश्यकता है कि राज्य स्कूलों (किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक) और सामुदायिक कॉलेजों (संयुक्त रूप से K–14 शिक्षा के रूप में संदर्भित) को न्यूनतम वार्षिक राशि—जिसे आमतौर पर प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी कहा जाता है—उपलब्ध कराए। न्यूनतम गारंटी का वित्तपोषण राज्य सामान्य फंड और स्थानीय संपत्ति कर राजस्व के संयोजन के माध्यम से होता है। कई वर्षों में, न्यूनतम गारंटी की गणना राज्य के सामान्य कोष राजस्व में परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। उन वर्षों में, जब राज्य के सामान्य फंड में काफी वृद्धि होती है तो गारंटी के भी काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। राज्य और स्थानीय वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा, जो स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए आबंटित किया जाता है, वह "अप्रतिबंधित" है, जिसका अर्थ है कि वे धन का उपयोग किसी भी शैक्षणिक प्रयोजन के लिए कर सकते हैं।

प्रस्ताव

नया कर राजस्व स्कूलों के वित्तपोषण और बजट संतुलन में मदद के लिए उपलब्ध है। उपाय की अस्थायी कर वृद्धि से उत्पन्न राजस्व को प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी की गणना में शामिल किया जाएगा—जो प्रत्येक वर्ष गारंटी में कई बिलियन डॉलर की वृद्धि करता है। इसलिए, इस नए राजस्व के एक हिस्से का इस्तेमाल उच्चतर स्कूल वित्तपोषण के लिए किया जाएगा और शेष राज्य के बजट के संतुलन में मदद करेगा। एक लेखा परिप्रेक्ष्य से, नए राजस्व को एक नवगठित राज्य खाते में जमा किया जाएगा, जिसे शिक्षा संरक्षण

खाता (EPA) कहा जाता है। खाते में धनराशि के 89 प्रतिशत को स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा और 11 प्रतिशत को सामुदायिक कॉलेजों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल और सामुदायिक कॉलेज इस धन का इस्तेमाल किसी शैक्षिक प्रयोजन के लिए कर सकते हैं। धन का वितरण उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि मौजूदा अप्रतिबंधित धन का किया जाता है, सिवाय इसके कि किसी स्कूल जिले को EPA फंड में प्रति छात्र $200 से कम प्राप्त नहीं होंगे और किसी भी सामुदायिक कॉलेज जिले को EPA फंड में प्रति पूर्णकालिक छात्र $100 से कम प्राप्त नहीं होंगे।

अगर उपाय को मंज़ूरी दे दी जाती है तो वित्तीय प्रभाव

2012–13 बजट योजना इस उपाय की मतदाता स्वीकृति पर निर्भर करती है। विधायिका और गवर्नर ने जून में 2012–13 वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट घाटे को संबोधित करने के लिए और साथ ही भविष्य के वर्षों में अनुमानित बजट घाटे को संबोधित करने के लिए एक बजट की योजना को अपनाया। 2012–13 की बजट योजना (1) मानती है कि मतदाता इस उपाय का अनुमोदन करते हैं और (2) इसके परिणामस्वरूप आने वाले राजस्व को राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च करती है। इस उपाय के द्वारा उत्पन्न राजस्व का एक बड़े हिस्से को स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों पर खर्च किया जाता है। इससे स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए 2012–13 में वित्तपोषण में बड़ी वृद्धि—वर्ष 2011–12 में $6.6 बिलियन की वृद्धि (14 प्रतिशत) की व्याख्या करने में मदद मिलती है। इस वृद्धि का लगभग अधिकाँश भाग पिछले वर्ष के व्यय का भुगतान करने और कुछ का इस्तेमाल K–14 भुगतानों में देरी को कम करने के लिए किया जाता है। बड़े अनुमानित बजट घाटे को देखते हुए, बजट योजना में कुछ स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों पर खर्च को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई, राज्य कर्मचारी मुआवजे में कमी, एक बारीय धन का उपयोग, और अन्य राज्य खातों से उधार लेना शामिल हैं।

2018–19 तक बजटों पर प्रभाव। इस उपाय के अतिरिक्त कर राजस्व 2018–19 तक राज्य के बजट को संतुलित करने में मदद के लिए उपलब्ध होंगे। इस उपाय से अतिरिक्त राजस्व 2018–19 तक सालाना कई बिलियन डॉलर उपलब्ध कराता है जो कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपलब्ध होगा—जिसमें मौजूदा राज्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण, K–14 शिक्षा भुगतान में देरी को समाप्त करना, और अन्य राज्य कर्ज का भुगतान करना शामिल हैं। विधायिका और गवर्नर की भविष्य की कार्रवाई इन निधियों के उपयोग का निर्धारण करेगी। उसी समय, ऊपरी आय करदाताओं की आय में उतार-चढ़ाव के कारण, इस उपाय के तहत राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव कुछ वर्षों में राज्य के बजट को उलझा सकते हैं। प्रस्तावित कर वृद्धि के समाप्त हो जाने के बाद, संबद्ध कर राजस्व के नुकसान से बाद के वर्षों में अतिरिक्त बजट दबाव आ सकता है।

अगर उपाय को नामंज़ूर कर दिया जाता है तो वित्तीय प्रभाव।

अगर मतदाता इस उपाय को नामंज़ूर कर देते हैं तो बैकअप बजट योजना खर्च कम कर देता है। यदि यह उपाय विफल रहता है, तो राज्य को प्रस्ताव की कर वृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में, 2012–13 की बजट योजना की आवश्यकता है कि इसके खर्च को $6 बिलियन तक कम किया जाए। इन ट्रिगर कटौतियों को, जो वर्तमान में राज्य के कानून में निर्धारित हैं, चित्र 3 में दिखाया गया है। लगभग सभी कटौतियाँ शिक्षा कार्यक्रमों में हैं—$5.4 बिलियन K–14 शिक्षा में और $500 मिलियन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में। K–14 कटौतियों में से, लगभग $3 बिलियन कटौती अप्रतिबंधित वित्तपोषण में से है। स्कूल और सामुदायिक कॉलेज इन कटौतियों पर विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें आरक्षित राशि में कटौती, स्कूलों के लिए अनुदेशात्मक साल को छोटा करना, और सामुदायिक कॉलेजों के लिए नामांकन को कम करना शामिल हैं। शेष $2.4 बिलियन की कटौती स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों में विलंबित भुगतान की राशि में 2011–12 के स्तर पर वृद्धि करेगी। इससे स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों की वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी की जरूरत प्रभावित हो सकती है, जो संभवतः अधिक अल्पकालिक उधार लेने को बढ़ावा देगी।

2018–19 तक बजटों पर प्रभाव। यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो राज्य के राजस्व 2018–19 तक प्रत्येक वर्ष उसके मुकाबले कई बिलियन डॉलर कम होंगे जब इसको स्वीकार कर लिया जाता। विधायिका और गवर्नर के भविष्य के कार्य निर्धारित करते हैं कि राज्य के बजट को राजस्व के इस निचले स्तर पर कैसे संतुलित किया जाए। भविष्य में राज्य के बजट को स्कूलों या अन्य कार्यक्रम के लिए कटौती कर, नए राजस्व, और एक बारीय कार्रवाई के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है।

चित्र 3

यदि मतदाता प्रस्ताव 30 को अस्वीकार कर देते हैं तो 2012–13 के खर्च में कटौती

(मिलियन में)

स्कूल एवं सामुदायिक कॉलेज	$5,354
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय	250
कैलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय	250
विकास सेवा विभाग	50
शहर पुलिस विभाग अनुदान	20
कैलफायर	10
DWR बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	7
स्थानीय जल सुरक्षा पैट्रोल अनुदान	5
मत्स्य एवं क्रीड़ा विभाग	4
पार्क एवं मनोरंजन विभाग	2
DOJ कानून प्रवर्तन कार्यक्रम	1
कुल	**$5,951**

DWR = जल संसाधन विभाग, DOJ = न्याय विभाग

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।

स्थानीय सरकारी कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

2011 में, राज्य ने कई कार्यक्रमों के प्रशासन और वित्तपोषण की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों (मुख्य रूप से काउंटियों) को हस्ताँतरित कर दी थी। हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों में कुछ वयस्क अपराधियों को जेल में डालना, पैरोलों का पर्यवेक्षण करना, और मादक द्रव्यों के सेवन की उपचार सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। इन नए दायित्वों के लिए भुगतान करने के लिए, विधायिका ने लगभग $6 बिलियन को राज्य कर राजस्व में से स्थानीय सरकारों को सालाना स्थानांतरित करने के लिए कानून पारित किया। इन निधियों में अधिकांश बिक्री कर के एक हिस्से को राज्य से स्थानीय सरकारों को हस्ताँतिरत करने से आते हैं।

प्रस्ताव

यह उपाय राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों के 2011 हस्तांतरण से संबंधित कुछ प्रावधानों को संविधान में स्थापित करता है।

चालू राजस्वों की स्थानीय सरकारों को गारंटी देता है। यह उपाय राज्य से 2011 (या समकक्ष फंड) में कर राजस्वों को स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित करने को जारी रखने की अपेक्षा करता है ताकि वे हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों के लिए भुगतान कर सकें। यह उपाय स्थानीय सरकारों को पुनर्निर्देशित बिक्री कर राजस्व को स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए न्यूनतम वित्तपोषण गारंटी की गणना से स्थायी रूप से बाहर करता है।

राज्य प्राधिकरण को कार्यक्रम आवश्यकताओं का विस्तार करने से रोकता है। स्थानीय सरकारों को भविष्य के किसी भी राज्य कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी जो 2011 में स्थानांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों का प्रशासन करने में स्थानीय लागत को बढ़ाते हैं, बशर्ते राज्य ने बढ़ी हुई लागत का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया हो।

राज्य से कुछ अप्रत्याशित कार्यक्रम लागत को साझा करने की अपेक्षा करता है। इस उपाय राज्य की आवश्यकता है कि राज्य उन किसी भी नई स्थानीय लागतों के हिस्से का भुगतान करे जो कुछ अदालती कार्रवाई और स्थानांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों से संबंधित संघीय विधियों या नियमों में परिवर्तन के फलस्वरूप आती हैं।

संभावित जनादेश अनुदान देयता को समाप्त करता है। संविधान के तहत, राज्य को स्थानीय सरकारों को उस समय प्रतिपूर्ति करनी होगी जब यह नई जिम्मेदारियों या "जनादेश" को उन पर लागू करता है। वर्तमान कानून के तहत, राज्य से स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त वित्तपोषण (जनादेश प्रतिपूर्ति) उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों में से कुछ के लिए भुगतान कर सकें। यह उपाय निर्दिष्ट करता है कि राज्य को ऐसे जनादेश प्रतिपूर्ति को उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

खुली बैठक अधिनियम लागत की राज्य प्रतिपूर्ति को समाप्त करता है। Ralph M. Brown अधिनियम की आवश्यकता है कि स्थानीय विधायी निकायों के सभी बैठकें खुली और सार्वजनिक हों। अतीत में, राज्य ने ब्राउन अधिनियम के कुछ प्रावधानों (जैसे कि सार्वजनिक बैठकों के लिए पहले और बाद का एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता) से उत्पन्न लागत के लिए स्थानीय सरकारों को प्रतिपूर्ति है। यह उपाय निर्दिष्ट करता है कि राज्य ब्राउन अधिनियम में खुली बैठक प्रक्रियाओं का पालन करने की लागत के लिए स्थानीय एजेंसियों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वित्तीय प्रभाव

राज्य सरकार। हस्तांतरित कार्यक्रमों के लिए राज्य लागतें उनसे अधिक हो सकती हैं जो अन्यथा होतीं क्योंकि यह उपाय (1) गारंटी देता है कि राज्य स्थानीय सरकारों को उनका भुगतान करने के लिए वित्तपोषण जारी रखेगा (2) अपेक्षा करता है कि राज्य भविष्य के संघीय कानून में परिवर्तन और अदालती मामलों से जुड़ी लागत का हिस्सा साझा करे, और (3) स्थानीय सरकारों को उन नए राज्य कानूनों और विनियमों से मना करने के लिए अधिकृत करता है जो उनकी लागत में वृद्धि करते हैं, जब तक कि राज्य अतिरिक्त धन प्रदान न करे। इन संभावित लागतों को आँशिक रूप से 2011 कार्यक्रम हस्तांतरण और ब्राउन अधिनियम प्रक्रियाओं में राज्य जनादेश देयता को समाप्त करने के इस उपाय की लागतों से ऑफसेट किया जाएगा। इन प्रावधानों के शुद्ध वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करना संभव नहीं है और यह निर्वाचित अधिकारियों और अदालतों द्वारा भविष्य की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। ऊपर चर्चा किए गए कारकों का स्थानीय सरकारों पर विपरीत वित्तीय प्रभाव होगा। यही कारण है, स्थानीय सरकार के राजस्व उससे अधिक होंगे जो वे अधिक होते, क्योंकि राज्य को (1) स्थानीय सरकारों 2011 में स्थानांतरित कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध कराना आवश्यक है और (2) भविष्य के संघीय और राज्य के कानून में परिवर्तन और अदालती मामलों के साथ जुड़ी लागतों का पूरा या आँशिक भुगतान करना आवश्यक हो सकता है। इन बढ़े हुए स्थानीय राजस्व को उपाय के उन प्रावधानों द्वारा आँशिक रूप से ऑफसेट किया जाएगा जो 2011 कार्यक्रम हस्ताँतरण और ब्राउन अधिनियम प्रक्रियाओं के लिए जनादेश प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के स्थानीय सरकार के अधिकार को समाप्त करते हैं। इन प्रावधानों के शुद्ध वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करना संभव नहीं है और यह निर्वाचित अधिकारियों और अदालतों द्वारा भविष्य की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

सारांश

अगर मतदाता इस उपाय का अनुमोदन करते हैं, राज्य बिक्री कर की दर में चार साल के लिए वृद्धि होगी और PIT में सात साल के लिए वृद्धि होगी, जिससे एक अनुमान के अनुसार औसतन 2012–13 और 2016–17 के बीच सालाना $6 बिलियन अतिरिक्त राज्य राजस्व पैदा होगा। (2011–12, 2017–18, और 2018–19 वित्त वर्षों के लिए राजस्व में छोटी वृद्धि होने की संभावना है)। इन राजस्वों का इस्तेमाल राज्य की 2012–13 बजट योजना के वित्तपोषण में मदद करने के लिए किया जाएगा और अगले सात वर्षों में बजट संतुलन में मदद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उपाय यह भी गारंटी देता है कि स्थानीय सरकारों को कुछ राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों को स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान करने के लिए 2011 में हस्ताँतरित राज्य के कर राजस्व का हिस्सा प्राप्त होना जारी रहेगा।

यदि मतदाता इस उपाय को अस्वीकार कर देते हैं, तो राज्य बिक्री कर और PIT दर में वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि इन कर दरों में वृद्धि से धन राज्य की 2012–13 बजट योजना निधि में उपलब्ध नहीं होगा, 2012–13 में राज्य के खर्च में लगभग $6 बिलियन की कमी होगी, शिक्षा से संबंधित कटौती में समान कटौती के साथ। भविष्य के वर्षों में, राज्य के राजस्व में उसके मुकाबले कई बिलियन डॉलर की कमी होगी जो इन उपायों को स्वीकार करने पर प्राप्त होते।

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।